चीन की छुट्टी! भारत बनेगा दुनिया का नया मैन्युफैक्चरिंग हब?

विषय सूची (Table of Contents):

>> ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब की ओर भारत क्या कहते हैं विदेशी निवेश के नए आंकड़े?...
>> भारत में एफडीआई की भारी उछाल अंकटाड की रिपोर्ट के सकारात्मक संकेत...
>> दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत का दबदबा...
>> लगातार बढ़ता निर्यात का दायरा इंजीनियरिंग गुड्स और व्यापार में शानदार वृद्धि...
>> इंजीनियरिंग निर्यात में दोहरे अंकों की बढ़त...
>> ग्लोबल वैल्यू चेन की हकीकत वियतनाम और चीन से भारत का वर्तमान फासला...
>> प्रतिद्वंद्वी देशों की स्थिति का तुलनात्मक विश्लेषण...
>> जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी विश्व बैंक के आंकड़े क्या बताते हैं?...
>> चीन और भारत के मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में अंतर...
>> चाइना प्लस वन रणनीति विदेशी कंपनियों के लिए भारत कैसे बन रहा है नया विकल्प?...
>> आसियान और भारत की ओर पूंजी का प्रवाह...
>> पीएलआई स्कीम और सरकारी नीतियां उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए उठाए गए अहम कदम...
>> ऑटोमैटिक रूट से आसान एफडीआई नियम...
>> भविष्य की चुनौती दुनिया का प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए क्या सुधार हैं...
>> अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)...

ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब की ओर भारत: क्या कहते हैं विदेशी न

दुनियाभर की वैश्विक अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन का ढांचा तेजी से बदल रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब विनिर्माण के लिए केवल एक देश पर निर्भर रहने के बजाय नए सुरक्षित विकल्पों की तलाश कर रही हैं। ऐसे में भारत दुनिया के प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में तेजी से उभरता नजर आ रहा है।

UNCTAD की ताजा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) 14% बढ़कर करीब 1.6 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र संस्था ने यह चेतावनी भी दी है कि वास्तविक निवेश गतिविधि अभी भी कई स्तरों पर सुस्त है और पूंजी प्रवाह रणनीतिक क्षेत्रों में सिमट रहा है।

इस वैश्विक उतार-चढ़ाव के बीच भारत की मजबूत स्थिति दुनिया के निवेशकों को आकर्षित कर रही है। भारत सरकार के नीतिगत सुधारों और बुनियादी ढांचे के विकास ने वैश्विक मंच पर देश की साख को मजबूती दी है। देश में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर बदलाव को समझने के लिए आपभूल जाओ पुरानी ट्रेन! भारत में आ रही फ्यूनीक्यूलर रेलवे और फ्लाई बसपर विस्तृत रिपोर्ट पढ़ सकते हैं।

भारत में एफडीआई की भारी उछाल: अंकटाड की रिपोर्ट के सकारात्मक

भारत के लिए सबसे बड़ा सकारात्मक संकेत विदेशी पूंजी प्रवाह यानी FDI में दर्ज की गई जबरदस्त तेजी है। UNCTAD की 2026 रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 के दौरान भारत में एफडीआई इनफ्लो 44% बढ़कर करीब 39 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यह आंकड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती मजबूती और निवेशकों के भरोसे को दर्शाता है।

दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत का दबदबा

दक्षिण एशिया क्षेत्र में कुल विदेशी निवेश 34 अरब डॉलर से बढ़कर 46 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। इस पूरे क्षेत्र में दर्ज की गई तेज वृद्धि की मुख्य प्रेरक शक्ति भारत ही रहा है।

>> वैश्विक FDI इनफ्लो:वर्ष 2025 में 1.6 ट्रिलियन डॉलर (14% की कुल वृद्धि)।

>> भारत में FDI का आंकड़ा:44% की सालाना बढ़त के साथ लगभग 39 अरब डॉलर।

>> दक्षिण एशिया का कुल निवेश:34 अरब डॉलर से उछलकर 46 अरब डॉलर दर्ज।

लगातार बढ़ता निर्यात का दायरा: इंजीनियरिंग गुड्स और व्यापार

विदेशी निवेश के साथ-साथ भारत का मर्चेंडाइज निर्यात आधार भी लगातार विस्तार ले रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल सामान निर्यात (Merchandise Exports) 437.70 अरब डॉलर दर्ज किया गया।

इंजीनियरिंग निर्यात में दोहरे अंकों की बढ़त

सरकारी Trade Analytics के 2026 के आंकड़ों के मुताबिक, इंजीनियरिंग सामानों के निर्यात में उत्साहजनक प्रदर्शन देखने को मिला है। जनवरी से मई 2026 के दौरान इंजीनियरिंग गुड्स का कुल निर्यात 54.13 अरब डॉलर दर्ज किया गया, जो बीते वर्ष की समान अवधि की तुलना में 10.87% अधिक है।

वैश्विक व्यापार और कूटनीतिक रणनीतियों में भारत का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक गतिविधियों परट्रंप की चाल: भारत को तेल और पाकिस्तान द्वीप प्लान का सच!का विश्लेषण देखा जा सकता है, जबकि खेल जगत में देश की निरंतर सफलता का उदाहरणभारत ने पाकिस्तान को रौंदा!में देखा जा सकता है।

ग्लोबल वैल्यू चेन की हकीकत: वियतनाम और चीन से भारत का वर्तमा

वैश्विक उत्पादन नेटवर्क में भारत की स्थिति मजबूत हो रही है, लेकिन ग्लोबल वैल्यू चेन (GVC) के मामले में वियतनाम और चीन जैसे देशों से अभी भी एक बड़ा अंतर बना हुआ है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 2022 में भारत की GVC से जुड़ी व्यापार हिस्सेदारी करीब 40% थी।

प्रतिद्वंद्वी देशों की स्थिति का तुलनात्मक विश्लेषण

इसके विपरीत, वियतनाम की GVC हिस्सेदारी 63% तक पहुंच चुकी है। इसका सीधा अर्थ यह है कि वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क में भारत की भागीदारी पहले से सुधरी है, लेकिन वियतनाम जैसे केंद्रित एक्सपोर्ट हब के स्तर तक पहुंचने के लिए अभी गति तेज करनी होगी।

>> भारत की GVC ट्रेड हिस्सेदारी:लगभग 40%।

>> वियतनाम की GVC ट्रेड हिस्सेदारी:लगभग 63%।

>> विश्व बैंक की सिफारिश:भारत को चीन, थाईलैंड और वियतनाम की बराबरी करने के लिए व्यापार व नीतिगत सुधारों की रफ्तार बढ़ानी होगी।

जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी: विश्व बैंक के आंकड

किसी भी देश को दुनिया का कारखाना बनने के लिए उसकी जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। विश्व बैंक के 2025 के आंकड़ों के मुताबिक, भारत की कुल जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हिस्सा वर्तमान में करीब 13% है।

चीन और भारत के मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में अंतर

चीन की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान लगभग 24% है, जो भारत से करीब दोगुना है। 2025 में भारत के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की कुल आर्थिक गतिविधि का मूल्य लगभग 533 अरब डॉलर आंका गया।

भारत के पास विशाल घरेलू बाजार और मजबूत उत्पादन क्षमता मौजूद है, लेकिन चीन की तरह एकीकृत और सशक्त सप्लायर इकोसिस्टम पूरी तरह विकसित होना अभी बाकी है।

चाइना प्लस वन रणनीति: विदेशी कंपनियों के लिए भारत कैसे बन र

कोविड महामारी और भू-राजनीतिक तनावों के बाद वैश्विक कंपनियों ने जोखिम कम करने के लिए China 1 मॉडल को अपनाया है। इसका उद्देश्य केवल चीन पर निर्भर रहने के बजाय कई देशों में अपने विनिर्माण संयंत्र स्थापित करना है।

आसियान और भारत की ओर पूंजी का प्रवाह

UNCTAD के अनुसार 2024 में चीन में आने वाले एफडीआई में 29% की भारी गिरावट दर्ज की गई, जबकि आसियान (ASEAN) देशों में एफडीआई 10% बढ़कर रिकॉर्ड 225 अरब डॉलर पहुंच गया। कंपनियां चीन को पूरी तरह छोड़ने के बजाय नए वैकल्पिक उत्पादन केंद्र तैयार कर रही हैं।

>> विशाल घरेलू बाजार:140 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं का मजबूत आधार।

>> युवा और कुशल कार्यबल:वैश्विक कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धी मानव संसाधन।

>> मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर:ऑटोमेशन और आधुनिक तकनीक का तेज प्रसार।

>> उभरते सेक्टर्स:इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फार्मास्युटिकल और इंजीनियरिंग में तेज विस्तार।

पीएलआई स्कीम और सरकारी नीतियां: उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए

केंद्र सरकार ने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं। इन पहलों के तहत विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर वित्तीय प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।

ऑटोमैटिक रूट से आसान एफडीआई नियम

व्यापार को सुगम बनाने के लिए सरकार ने अधिकांश विनिर्माण क्षेत्रों में 100% एफडीआई को ऑटोमैटिक रूट के तहत मंजूरी दे दी है। इसके तहत विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए पूर्व प्रशासनिक अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, जिससे निवेश प्रक्रिया बेहद सरल हो गई है।

भविष्य की चुनौती: दुनिया का प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब बनने क

भारत को वैश्विक विनिर्माण का वास्तविक पावरहाउस बनने के लिए अभी भी कुछ महत्वपूर्ण मोर्चों पर सुधार की आवश्यकता है। उत्पादन लागत को कम करना और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को वैश्विक मानकों के अनुरूप ढालना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए।

यदि भारत समय पर लॉजिस्टिक्स लागत, कामगारों के कौशल विकास, आधुनिक तकनीक के हस्तांतरण और निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार कर लेता है, तो China 1 रणनीति के तहत भारत न केवल एक वैकल्पिक केंद्र बनेगा, बल्कि दुनिया का शीर्ष मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभरेगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

UNCTAD रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत में एफडीआई इनफ्लो 44% बढ़कर लगभग 39 अरब डॉलर तक पहुंच गया है।

China 1 रणनीति के तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन के अलावा अन्य देशों में विनिर्माण केंद्र स्थापित कर रही हैं, जिससे भारत को बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार मिल रहा है।

विश्व बैंक के 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी करीब 13% (लगभग 533 अरब डॉलर) है, जबकि चीन में यह लगभग 24% है।

विश्व बैंक के अनुसार भारत की GVC ट्रेड हिस्सेदारी करीब 40% है, जबकि वियतनाम 63% हिस्सेदारी के साथ आगे बना हुआ है।

सरकारी Trade Analytics के अनुसार जनवरी-मई 2026 में इंजीनियरिंग गुड्स का निर्यात 10.87% बढ़कर करीब 54.13 अरब डॉलर दर्ज किया गया।

कंपनियां वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर PLI Scheme guidelines की PDF डाउनलोड कर सकती हैं और ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकती हैं।

अधिकांश मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑटोमैटिक रूट के जरिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है, जिसमें सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती।

भारत को मुख्य रूप से लॉजिस्टिक्स लागत घटाने, वर्कफोर्स स्किलिंग, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी अपनाने और निर्यात प्रक्रियाओं को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की आवश्यकता है।